RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

After studying this chapter, the learners will

- **understand rural development and the major issues associated with it**
- **appreciate how crucial the development of rural areas is for India's overall development**
- **understand the critical role of credit and marketing systems in rural development**
- **learn about the importance of diversification of productive activities to sustain livelihoods**
- **understand the significance of organic farming in sustainable development.**

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप

- ग्रामीण विकास और उससे जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों को समझ सकेंगे;
- ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भारत के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, यह जानेंगे;
- ग्रामीण विकास में साख और विपणन की महत्त्वपूर्ण भूमिका को समझंगे;
- आजीविका के स्थायित्व के लिए उत्पादक गतिविधियों में विविधता के महत्व को समझंगे;
- धारणीय विकास में जैविक कृषि के महत्व को समझंगे।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

INTRODUCTION

In Chapter 4, we studied how poverty was a major challenge facing India. We also came to know that the majority of the poor live in rural areas where they do not have access to the basic necessities of life.

परिचय

अध्याय 4 में हमन पढ़ा कि किस प्रकार निर्धनता भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने यह भी जाना कि हमारे अधिकतर निर्धन देशवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहां उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ भी सुलभ नहीं हो पाती हैं।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

Agriculture is the major source of livelihood in the rural sector. Mahatma Gandhi once said that the real progress of India did not mean simply the growth and expansion of industrial urban centres but mainly the development of the villages. This idea of village development being at the centre of the overall development of the nation is relevant even today. Why is this so? Why should we attach such significance to rural development when we see around us fast growing cities with large industries and modern information technology hubs? It is because more than two-third of India's population depends on agriculture that is yet to become productive enough to provide for them; one-fourth of rural India still lives in abject poverty. That is the reason why we have to see a developed rural India if our nation has to realise real progress.

ग्रामीण क्षेत्रकों में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। कभी महात्मा गाँधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गाँवों के विकास से है। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एसा क्यों है? हम अपने चारों ओर बड़े उद्योगों तथा सूचना-प्रौद्योगिकी केंद्रों से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं, फिर भी ग्रामीण विकास को ही इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर है कि आज भी भारत की दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, जिसकी उत्पादकता अभी भी इतनी ही है कि उससे सबका निर्वाह भी नहीं हो पाता। इसी कारण से देश की एक-चौथाई जनता अभी भी घोर निर्धनता में रहती है। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं, तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

WHAT IS RURAL DEVELOPMENT?

Rural development is a comprehensive term. It essentially focuses on action for the development of areas that are lagging behind in the overall development of the village economy. Some of the areas which are challenging and need fresh initiatives for development in rural India include

ग्रामीण विकास क्या है?

'ग्रामीण विकास' एक व्यापक शब्द है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड गए हैं। भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी हुई है, वे इस प्रकार हैं; मानव संसाधनों का विकास जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

- **Development of human resources including – literacy, more specifically, female literacy, education and skill development – health, addressing both sanitation and public health**
- **Land reforms**
- **Development of the productive resources of each locality**
- **Infrastructure development like electricity, irrigation, credit, marketing, transport facilities including construction of village roads and feeder roads to nearby highways, facilities for agriculture research and extension, and information dissemination**
- **Special measures for alleviation of poverty and bringing about significant improvement in the living conditions of the weaker sections of the population emphasising access to productive employment opportunities**

- साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा और कौशल का विकास। ख स्वास्थ्य, जिसमें स्वच्छता और जन–स्वास्थ्य दोनों शमिल हैं।
- भूमि–सुधार।
- प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास। ख आधारिक संरचना का विकास जैसे– बिजली, सिंचाई, साख(ऋण), विपणन, परिवहन सुविधाएँ – ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित राजमार्ग की पोषक सड़कें बनाना, कृषि अनुसंधान विस्तार और सूचना प्रसार की सुविधाएँ।
- निर्धनता निवारण और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय, जिसमें उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

It was observed in an earlier chapter that although the share of agriculture sector's contribution to GDP was on a decline, the population dependent on this sector did not show any significant change. Further, after the initiation of reforms, the growth rate of agriculture sector decelerated to about 3 per cent per annum during the 1991-2012, which was lower than the earlier years. In recent years, this sector has become volatile. During 2014-15, the GVA growth rate of agriculture and its allied sectors was less than one per cent.

हमने पिछले अध्याय में यह भी देखा है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है, किंतु कृषि पर आश्रित जनसंख्या अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। यही नहीं, नए सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद तो 1991–2012 में कृषि की संवृद्धि दर घट कर 3 प्रतिशत ही रह गई, हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अस्थिरता आई है, 2014–16 के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की सकल मूल्य की वृद्धि दर एक प्रतिशत से भी कम थी।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

Scholars identify decline in public investment since 1991 as the major reason for this. They also argue that inadequate infrastructure, lack of alternate employment opportunities in the industry or service sector, increasing casualisation of employment etc., further impede rural development

जो पिछले वर्षों से भी कम है। अनेक अर्थशास्त्री 1991 के बाद से सार्वजनिक निवेश में आई गिरावट को इसका कारण मानते हैं। उनका यह भी विचार है कि अपर्याप्त आधारिक संरचना, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रक में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के अभाव और अनियत रोजगार में वृद्धि आदि के कारण भी ग्रामीण विकास में बाधाएँ आ रही हैं।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

CREDIT AND MARKETING IN RURAL AREAS

Credit: Growth of rural economy depends primarily on infusion of capital, from time to time, to realise higher productivity in agriculture and non-agriculture sectors. As the time gestation between crop sowing and realisation of income after production is quite long, farmers borrow from various sources to meet their initial investment on seeds, fertilisers, implements and other family expenses of marriage, death, religious ceremonies etc.

ग्रामीण क्षेत्रकों में साख और विपणन

साख: कृषि अर्थव्यवस्था की संवृद्धि समय – समय पर कृषि और गैर–कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूँजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। खेतों में बीजारोपण से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। यही नहीं, उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह खर्च और शादी, मृत्यु तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कर्ज़ का ही आसरा रहता है।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

At the time of independence, moneylenders and traders exploited small and marginal farmers and landless labourers by lending to them on high interest rates and by manipulating the accounts to keep them in a debt-trap. A major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multiagency approach to adequately meet the needs of rural credit. Later, the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) was set up in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all institutions involved in the rural financing system. The Green Revolution was a harbinger of major changes in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of rural credit towards productionoriented lending.

स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे/सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों से बहुत ऊँची दर से ब्याज वसूलने और ऋण–खाते में हेराफेरी का एसा कुचक्र चला रहे थे, कि वे कभी भी ऋणपाश से मुक्त नहीं हो पाते थे। भारत ने 1969 में सामाजिक बैंकिग आरंभ कर इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। ग्रामीण साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहु–संस्था व्यवस्था का सहारा लिया गया। आगे चलकर 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। हरित क्रांति ने भी ग्रामीण साख व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया है, क्योंकि इसने ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों को उत्पादक ऋणों की ओर उन्मुख कर विविधता प्रदान की।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

The institutional structure of rural banking today consists of a set of multi-agency institutions, namely, commercial banks, regional rural banks (RRBs), cooperatives and land development banks. They are expected to dispense adequate credit at cheaper rates. Recently, Self-Help Groups (henceforth SHGs) have emerged to fill the gap in the formal credit system because the formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but has also not been fully integrated into the overall rural social and community development.

आज ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में अनेक बहु-एजेन्सी संस्थान जैसे, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, (आर.आर.बी.)सहकार तथा भूमि विकास बैंक सम्मिलित हैं। ये सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की पूर्ति करना चाहती है । हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करते हुए स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का भी ग्रामीण साख व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी, बल्कि ग्रामीण सामाजिक तथा सामुदायिक विकास में पूरी तरह समन्वित साबित हुई हैं।

The SHGs promote thrift in small proportions by a minimum contribution from each member. From the pooled money, credit is given to the needy members to be repayable in small instalments at reasonable interest rates. By May 2019, nearly 6 crore women in India have become member in 54 lakh women SHGs. About ` 10-15,000 per SHG and another `2.5 lakhs per SHG as a Community Investment Support Fund (CISF) are provided as part of renovating fund to take up self employement for income generation. Such credit provisions are generally referred to as micro-credit programmes. SHGs have helped in the empowerment of women. It is alleged that the borrowings are mainly confined to consumption purposes

इस प्रकार एकत्र राशि में से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है। उस ऋण की राशि छोटी-छोटी (आसान) किश्तों में लौटाई जाती है। ब्याज की दर भी उचित रखी जाती है। मई, 2019 तक 54 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) में लगभग 6 करोड महिला सदस्य हैं। लगभग 10,000-15,000 रुपये प्रति SHG और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति SHG को परिक्रमी निधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता कोष (CISF) का सृजन किया जाता है। जिसके फलस्वरूप आय सृजन हेतु महिला सदस्य स्वरोजगार को अपना सकती है। इस प्रकार की साख उपलब्धता को अतिलघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के सशक्तीकरण में सहायता की है। इन ऋण-सुविधाओं का प्रयोग किसी न किसी प्रकार के उपभोग के लिए ही हो रहा है -

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

Rural Banking — a Critical Appraisal:

Rapid expansion of the banking system had a positive effect on rural farm and non-farm output, income and employment, especially after the green revolution — it helped farmers to avail services and credit facilities and a variety of loans for meeting their prodution needs. Famines became events of the past; we have now achieved food security which is reflected in the abundant buffer stocks of grains.

ग्रामीण बैंकिंग: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन: बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव रहा है, विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद से किसानों को साख सेवाएँ और सुविधाएँ देने तथा उनकी उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने में इन्होंने सहायता दी है। अब तो अकाल बीते यग की बात हो गई है; हम खाद्य सुरक्षा की उस मंजिल पर पहुँच चुके हैं कि हमारे अपने सुरक्षित भंडार भी बहुत पर्याप्त माने जा रहे हैं।

With the possible exception of the commercial banks, other formal institutions have failed to develop a culture of deposit mobilisation — lending to worthwhile borrowers and effective loan recovery. Agriculture loan default rates have been chronically high. Why farmers failed to pay back loans? It is alleged that farmers are deliberately refusing to pay back loans.

संभवत: व्यावसायिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी औपचारिक साख संस्थाएँ जमा प्रवाह की संस्कृति को विकसित नहीं कर पायी हैं। न ये सही ऋण चाहने वालों को ऋण दे पाती हैं और न ही इनकी कोई प्रभावपूर्ण ऋण वसूली व्यवस्था बन पाई है। कृषि ऋणों की वसूली नहीं हो पाने की समस्या बहुत गंभीर है। कृषि ऋण का भुगतान न कर पाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। किसान ऋण का भुगतान करने में क्यों असफल रहे हैं? स्पष्ट है कि किसान बड़े पैमाने पर ऋण अदा करने से इन्कार कर रहे हैं।

Thus, the expansion and promotion of the rural banking sector has taken a backseat after reforms. To improve the situation, it is suggested that banks need to change their approach from just being lenders to building up relationship banking with the borrowers.

इसलिए, सुधारों के बाद से बैंकिंग क्षेत्रक के प्रसार एवं उन्नति में कमी हुई है। स्थिति में सुधार लाने के लिए यह बैंकों को अपनी कार्य-प्रणाली में बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि वे केवल ऋणदाता और ऋण लेने वालों के बीच में एक सेतु का काम करें।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

The Poor Women's Bank

'Kudumbashree' is a women-oriented community-based poverty reduction programme being implemented in Kerala. In 1995, a thrift and credit society was started as a small savings bank for poor women with the objective to encourage savings. The thrift and credit society mobilised Rs 1 crore as thrift savings. These societies have been acclaimed as the largest informal banks in Asia in terms of participation and savings mobilised.

निर्धन महिलाओं का बैंक

केरल प्रांत में महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धनता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका नाम 'कुटुंब श्री' है। 1995 में सरकारी बचत एवं साख सोसायटी के रूप में गरीब महिलाओं के लिए इस बचत बैंक की स्थापना की गई थी। इस बचत एवं साख सोसायटी ने छोटी-छोटी बचतों को मिलाकर एक करोड रुपये की विशाल राशि एकत्र कर ली। इसे अब सदस्य संख्या और संगठित बचत के आधार पर एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक माना जाता है।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

AGRICULTURAL MARKET SYSTEM

The mechanism through which these goods reach different places depends on the market channels. Agricultural marketing is a process that involves the assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agricultural commodities across the country

कृषि विपणन व्यवस्था

इन्हें हम तक पहुँचाने का माध्यम बाज़ार व्यवस्था है। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

Prior to independence, farmers, while selling their produce to traders, suffered from faulty weighing and manipulation of accounts. Farmers who did not have the required information on prices prevailing in markets were often forced to sell at low prices. They also did not have proper storage facilities to keep back their produce for selling later at a better price.

स्वतंत्रतापूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तोल में हेरा फेरी तथा खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। प्राय: किसानों को बाज़ार में प्रचलित भावों का पता नहीं होता था और उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था। उनके पास अपना माल रखने के लिए अच्छी भंडारण सुविधाएँ नहीं होती थीं, अत: वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं रख पाते थे।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

The first step was regulation of markets to create orderly and transparent marketing conditions. By and large, this policy benefited farmers as well as consumers. However, there is still a need to develop about 27,000 rural periodic markets as regulated market places to realise the full potential of rural markets

पहला कदम व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाज़ार का नियमन करना था। इस नीति से बहुत दूर तक कृषक और उपभोक्ता, दोनों ही वर्ग लाभांवित हुए हैं। हालाँकि, लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियत मंडियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्राम्य क्षेत्रों की मंडियों की वास्तविक क्षमताओं का लाभ उठा पाना संभव हो।

Second component is provision of physical infrastructure facilities like roads, railways, warehouses, godowns, cold storages and processing units. The current infrastructure facilities are quite inadequate to meet the growing demand and need to be improved. Cooperative marketing, in realising fair prices for farmers' products, is the third aspect of government initiative.

दूसरा महत्वपूर्ण उपाय सड़कों, रेलमार्गों, भंडारगृहों गोदामों, शीतगृहों और प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भौतिक आधारिक संरचनाओं का प्रावधान किया जाना है। किंतु, अभी तक वर्तमान आधारिक सुविधाएँ बढ़ती माँग को देखते हुए नितांत अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य सुलभ कराना है।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

The success of milk cooperatives in transforming the social and economic landscape of Gujarat and some other parts of the country is testimony to the role of cooperatives. However cooperatives have received a setback during the recent past due to inadequate coverage of farmer members, lack of appropriate link between marketing and processing cooperatives and inefficient financial management.

गुजरात तथा देश के अन्य कई भागों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने ग्रामीण अंचलों के सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया है। किंतु, अभी भी कुछ स्थानों पर सहकारिता आंदोलन में कुछ कमियां दिखाई देती हैं। इनके कारण हैं: सभी कृषकों को सहकारिताओं में शामिल नहीं कर पाना, विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों के बीच संबंध सूत्रों का नहीं होना और अकुशल वित्तीय प्रबंधन।

The fourth element is the policy instruments like

(i) assurance of minimum support prices (MSP) for agricultural products

(ii) maintenance of buffer stocks of wheat and rice by Food Corporation of India and

(iii) distribution of food grains and sugar through PDS. These instruments are aimed at protecting the income of the farmers and providing foodgrains at a subsidised rate to the poor.

चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत साधन हैं– जैसे:

(क) कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार की रख रखाव और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था) के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी का वितरण। इन साधनों का ध्येय क्रमशः किसानों को उपज के उचित दाम दिलाना तथा गरीबों को सहायिकी युक्त (subsidised) कीमत पर वस्तुएँ उपलब्ध कराना रहा है।

despite government intervention, private trade (by moneylenders, rural political elites, big merchants and rich farmers) predominates agricultural markets. The need for government intervention is imminent particularly when a large share of agricultural products, is handled by the private sector.

सरकार के इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों, (साहूकारों, ग्रामीण राजनीतिज्ञ सामंतों, बड़े व्यापारियों तथा अमीर किसानों) का वर्चस्व बना हुआ है। इसके लिए जरूरी है सरकार की मध्यस्थता, खासकर जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्रक का नियंत्रण होता है। सरकारी संस्थाएँ और सहकारिताएँ सकल कृषि उत्पादन के मात्र 10 प्रतिशत अंश के आदान-प्रदान में सफल हो पा रही हैं - शेष अभी भी निजी व्यापारियों के हाथों में ही हैं।

Emerging Alternate Marketing Channels: It has been realised that if farmers directly sell their produce to consumers, it increases their incomes. Some examples of these channels are Apni Mandi (Punjab, Haryana and Rajasthan); Hadaspar Mandi (Pune); Rythu Bazars (vegetable and fruit markets in Andhra Pradesh and Telangana) and Uzhavar Sandies (farmers markets in Tamil Nadu). Further, several national and multinational fast food chains are increasingly entering into contracts/ alliances with farmers to encourage them to cultivate farm products (vegetables, fruits, etc.) of the desired quality by providing them with not only seeds and other inputs but also assured procurement of the produce at predecided prices.

वैकल्पिक क्रय-विक्रय माध्यमों का प्रादुर्भाव: अब यह बात सभी अनुभव कर रह हैं कि यदि किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सकें तो उसे अधिक आय प्राप्त होगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी, पुणे की हाड़पसार मंडी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा की रायथूबाज नामक फल सब्जी मंडियाँ तथा तमिलनाडु की उझावरमंडी के कृषक बाज़ार, इस प्रकार से विकसित हो रहे वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम के कुछ उदाहरण हैं। ये सब कुछ वैकल्पिक विपणन संरचनाओं के उदाहरण हैं। यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ (फास्ट फूड)बनाने वाली कंपनियां भी अब किसानों के साथ कृषि-उत्पाद की खेती (फल-सब्जियों) के लिए उत्पादकों से अनुबंध कर रही हैं। ये किसानों को उचित बीज तथा अन्य आगत तो उपलब्ध कराती ही हैं; उन्हें पूर्व-निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती हैं।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

DIVERSIFICATION INTO PRODUCTIVE ACTIVITIES

Diversification includes two aspects - one relates to change in cropping pattern and the other relates to a shift of workforce from agriculture to other allied activities (livestock, poultry, fisheries etc.) and non-agriculture sector. The need for diversification arises from the fact that there is greater risk in depending exclusively on farming for livelihood. Diversification towards new areas is necessary not only to reduce the risk from agriculture sector but also to provide productive sustainable livelihood options to rural people.

उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण

विविधीकरण के दो पहलू हैं: एक पहलू तो फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा पहलू श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों (जैसे पशुपालन, मुर्गी और मत्स्य पालन आदि) तथा गैर-कृषि क्षेत्रक में लगाना है। इस विविधीकरण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाने में जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। अत: विविधीकरण द्वारा हम न केवल खेती से जोखिम को कम करने में सफल होंगे बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक और वैकल्पिक धारणीय आजीविका के अवसर भी उपलब्ध हो पाएँगे।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

Much of the agricultural employment activities are concentrated in the Kharif season. But during the Rabi season, in areas where there are inadequate irrigation facilities, it becomes difficult to find gainful employment. Therefore expansion into other sectors is essential to provide supplementary gainful employment and in realising higher levels of income for rural people to overcome poverty and other tribulations. Hence, there is a need to focus on allied activities, non-farm employment and other emerging alternatives of livelihood, though there are many other options available for providing sustainable livelihoods in rural areas

देश में अधिकांश कृषि रोजगार खरीफ की फसल से जुड़ा रहता है, किंतु रबी की फसल के मौसम में तो जहा पर्याप्त ' सिंचाई सुविधाए नहीं हैं ' , उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार दुर्लभ हो जाता है। अत: अन्य प्रकार की उत्पादक और लाभप्रद गतिविधियों में प्रसार के माध्यम से ही हम ग्रामीण जनसमुदाय को अधिक आय कमाकर गरीबी तथा अन्य विषम परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बना पाएँगे। अत: जरूरत संबद्ध गतिविधियों, गैर कृषि रोजगार तथा नये वैकल्पिक आजीविका स्त्रोतों के विकास पर ध्यान देने की है। वैसे अब ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नए धारणीय आजीविका विकल्पों का विकास हो रहा है।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

As agriculture is already overcrowded, a major proportion of the increasing labour force needs to find alternate employment opportunities in other non-farm sectors. Non-farm economy has several segments in it; some possess dynamic linkages that permit healthy growth while others are in subsistence, low productivity propositions. The dynamic sub-sectors include agro-processing industries, food processing industries, leather industry, tourism, etc. Those sectors which have the potential but seriously lack infrastructure and other support include traditional home-based industries like pottery, crafts, handlooms etc. Majority of rural women find employment in agriculture while men generally look for non-farm employment.

कृषि क्षेत्र पर तो पहले ही से बहुत बोझ है। अत: बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए अन्य गैर-कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। गैर-कृषि अर्थतंत्र में अनेक घटक होते हैं। कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशील अंतसंबंध होते हैं और उनमें 'स्वस्थ' संवृद्धि की संभावनाएँ रहती हैं, किंतु अनेक घटक तो निम्न उत्पादकता वाले निर्वाह मात्र की व्यवस्था कर पाते हैं। गतिशील उपघटकों में कृषि-प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग तथा पर्यटन आदि सम्मिलित हैं। कुछ एसे क्षेत्रक भी हैं जिनमें संभावनाएँ तो विद्यमान हैं, पर जिनके लिए संरचनात्मक सुविधाएँ तथा अन्य सहायक कार्यों का नितांत अभाव है। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योगों को रख सकते हैं जैसे, मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्प कलाएँ, हथकरघा आदि। यद्यपि, अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ कृषि में रोजगार प्राप्त करती हैं, जबकि पुरुष गैर-कृषि रोजगार की तलाश में है।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

Animal Husbandry: In India, the farming community uses the mixed crop-livestock farming system — cattle, goats, fowl are the widely held species. Livestock production provides increased stability in income, food security, transport, fuel and nutrition for the family without disrupting other food-producing activities. Today, livestock sector alone provides alternate livelihood options to over 70 million small and marginal farmers including landless labourers. A significant number of women also find employment in the livestock sector.

पशुपालन: भारत के किसान समुदाय प्राय: मिश्रित कृषि पशु धन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। इसमें गाय–भैंस, बकरियां और मुर्गी–बत्तख आदि बहुतायत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। मवेशियों के पालन से परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि की व्यवस्था भी परिवार की अन्य खाद्य उत्पादक (कृषक) गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त हो जाती हैं। आज पशुपालन क्षेत्रक देश के 7 करोड छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं। इस क्षेत्रक में महिलाएँ भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा रही हैं।

Poultry accounts for the largest share with 58 per cent followed by others. Other animals which include camels, asses, horses, ponies and mules are in the lowest rung. India had about 300 million cattle, including 108 million buffaloes in 2012.

इसमें सबसे बड़ा अंश 58 प्रतिशत तो मुर्गी पालन का है। अन्य पशुओं में ऊँट, गधे, घोड़े आते हैं। सबसे निम्न स्तर खच्चरों तथा टट्टुओं का है। 2012 में भारत में 300 मिलियन मवेशी थे, उनमें से 108 मिलियन भैंसें थीं।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

Performance of the Indian dairy sector over the last three decades has been quite impressive. Milk production in the country has increased by about ten times between 1951-2016. This can be attributed mainly to the successful implementation of 'Operation Flood'

पिछले तीन दशकों में भारत के डेयरी उद्योग ने बहुत शानदार प्रगति दिखाई है, 1951–2016 की अवधि में देश में दुग्ध उत्पादन लगभग दस गुना बढ गया है। इसका मुख्य श्रेय 'ऑपरेशन फ्लड' (दूध की बाढ़) को दिया जाता है।

In this system the farmers are assured of a fair price and income from the supply of milk to urban markets. As pointed out earlier Gujarat state is held as a success story in the efficient implementation of milk cooperatives which has been emulated by many states. Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Punjab and Rajasthan, are major milk producing states. Meat, eggs, wool and other by- products are also emerging as important productive sectors for diversification.

उसकी गुणवत्ता के अनुसार प्रसंस्करण करते हैं और फिर उसे शहरी केंद्रों में सहकारिताओं के माध्यम से बेचा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया था, गुजरात प्रदेश ने दुग्ध सहकारिताओं का एक विलक्षण प्रतिमान विकसित किया है– देश के अन्य अनेक प्रांतों में उसी का अनुकरण किया जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट, पंजाब और राजस्थान प्रमुखत: दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। अब मांस, अंडे तथा ऊन आदि भी उत्पादन क्षेत्र के विविधीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सह–उत्पाद सिद्ध हो रहे हैं।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

Fisheries: The fishing community regards the water body as 'mother' or 'provider'. The water bodies consisting of sea, oceans, rivers, lakes, natural aquatic ponds, streams etc. are, therefore, an integral and life-giving source for the fishing community. In India, after progressive increase in budgetary allocations and introduction of new technologies in fisheries and aquaculture, the development of fisheries has come a long way.

मत्स्य पालन: मछुआरों के समुदाय तो प्रत्येक जलागार को 'मां' या 'दाता' मानते हैं। सागर–महासागर, सरिताएँ, झोलें, प्राकृतिक तालाब, प्रवाह आदि सभी जलागार मछुआरों के समाज के लिए निश्चित जीवन दीपक स्रोत बन जाते हैं। भारत में बजटीय प्रावधानों में वृद्धि और मत्स्य पालन एवं जल कृषिकी में नवीन प्रौद्यागिकी के प्रवेश के बाद से मत्स्य उद्योग ने विकास की नई मंजिलें तय की हैं।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

Presently, fish production from inland sources contributes about 65 per cent to the total value of fish production and the balance 35 per cent comes from the marine sector (sea and oceans). Today total fish production accounts for 0.9 per cent of the total GDP. In India, West Bengal, Andhra Pradesh, Kerala, Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu are major fish producing states. A large share of fishworker families are poor. Rampant underemployment, low per capita earnings, absence of mobility of labour to other sectors and a high rate of illiteracy and indebtedness are some of the major problems fishing community face today.

आजकल देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का 65 प्रतिशत अंतर्वर्ती क्षेत्रों से तथा 35 प्रतिशत महासागरीय क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। यह मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत है। मत्स्य उत्पादकों में प्रमुख राज्य पं. बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट और तमिलनाडु हैं। मछुआरों के परिवारों का एक बड़ा हिस्सा निधंन है। इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार, निम्न प्रतिव्यक्ति आय, अन्य कार्यों की ओर श्रम के प्रवाह का अभाव, उच्च निरक्षरता दर तथा गंभीर ऋण–ग्रस्तता इन मछुआरा समुदाय से आजकल जूझ रहे हैं।

Even though women are not involved in active fishing, about 60 per cent of the workforce in export marketing and 40 per cent in internal marketing are women. There is a need to increase credit facilities through cooperatives and SHGs for fisherwomen to meet the working capital requirements for marketing.

यद्यपि महिलाएँ मछलियां पकड़ने के काम में नहीं लगी हैं, पर 60 प्रतिशत निर्यात और 40 प्रतिशत आंतरिक मत्स्य व्यापार का संचालन उन्हीं के हाथों में है। विपणन के लिए आवश्यक पूँजी जुटाने में मछुआरा समुदाय की महिलाओं की सहायता के लिए सहकारिताओं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से साख सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता अब अनुभव हो रही है।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

Horticulture: Blessed with a varying climate and soil conditions, India has adopted growing of diverse horticultural crops such as fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crops. These crops play a vital role in providing food and nutrition, besides addressing employment concerns. Horticulture sector contributes nearly one-third of the value of agriculture output and six per cent of Gross Domestic Product of India.

उद्यान विज्ञान (बागवानी): प्रकृति ने भारत को ऋतुओं और मृदा की विविधता से संपन्न किया है। उसी के आधार पर भारत ने अनेक प्रकार के बागान उत्पादों को अपना लिया है। इनमें प्रमुख हैं – फल-सब्जियां, रेशेदार फसलें, औषधीय तथा सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफी इत्यादि। ये सभी फसलें रोजगार के साथ-साथ भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में भी बड़ा योगदान दे रही हैं। भारत में बागवानी क्षेत्रक समस्त कृषि उत्पाद का लगभग एक तिहाई और सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत है।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

India has emerged as a world leader in producing a variety of fruits like mangoes, bananas, coconuts, cashew nuts and a number of spices and is the second largest producer of fruits and vegetables. Economic condition of many farmers engaged in horticulture has improved and it has become a means of improving livelihood for many unprivileged classes. Flower harvesting, nursery maintenance, hybrid seed production and tissue culture, propagation of fruits and flowers and food processing are highly remunerative employment options for women in rural areas

भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और अनेक मसालों के उत्पादन में तो आज विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। कुल मिलाकर फल-सब्जियों के उत्पादन में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है। बागवानी में लगे कितने ही कृषकों की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। ये उद्योग अब अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका को बेहतर बनाने में सहायक हो गए हैं। पुष्परोपण, पौधशाला की देखभाल, संकर बीजों का उत्पादन, ऊतक -संवर्धन, फल फूलों का संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण महिलाओं के लिए अब अधिक आय वाले रोजगार बन गए हैं।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

Though, in terms of numbers, our livestock population is quite impressive but its productivity is quite low as compared to other countries. It requires improved technology and promotion of good breeds of animals to enhance productivity. Improved veterinary care and credit facilities to small and marginal farmers and landless labourers would enhance sustainable livelihood options through livestock production. Production of fisheries has already increased substantially.

यद्यपि संख्याबल की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देशों की तुलना में उसके उत्पादक का स्तर बहुत ही न्यून है। यहां भी पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए नई उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर पशुधन उत्पादन के माध्यम से भी धारणीय रोजगार विकल्प का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। मछली पालन में पहले से ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है तथापि मछली पालन के आधिक्य से संबंधित प्रदूषण की समस्या को नियमित और नियंत्रित करना आवश्यक है।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

Welfare programmes for the fishing community have to be reoriented in a manner which can provide long-term gains and sustenance of livelihoods. Horticulture has emerged as a successful sustainable livelihood option and needs to be encouraged significantly. Enhancing its role requires investment in infrastructure like electricity, cold storage systems, marketing linkages, small-scale processing units and technology improvement and dissemination.

मछुआरा समुदाय के कल्याण कार्यों की इस प्रकार पुनर्रचना करनी होगी कि उनके लाभ दीर्धकालिक हों और उनकी आजीविका का साधन बन सकें। बागवानी एक धारणीय रोजगार विकल्प के रूप में उभरा है और इसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसे और बढ़ाव देने के लिए बिजली, शीतगृह व्यवस्था, विपणन माध्यमों के विकास, लघु स्तरीय प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और प्रौद्योगिकी के उन्नयन और प्रसार के लिए आधारिक संरचनाओं में निवेश की आवश्यकता है।

Other Alternate Livelihood Options: **The IT has revolutionised many sectors in the Indian economy. There is broad consensus that IT can play a critical role in achieving sustainable development and food security in the twenty-first century. Governments can predict areas of food insecurity and vulnerability using appropriate information and software tools so that action can be taken to prevent or reduce the likelihood of an emergency.**

अन्य रोजगार/आजीविका विकल्प: सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रकों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। 21वीं शताब्दी में देश में खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास में सूचना प्रौद्योगिकी निर्णायक योगदान दे सकती है। सूचनाओं और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सरकार सहज ही खाद्य असुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्रों का समय रहते पूर्वानुमान लगा सकती है।

It also has a positive impact on the agriculture sector as it can disseminate information regarding emerging technologies and its applications, prices, weather and soil conditions for growing different crops etc. Though IT is, by itself, no catalyst of change but it can act as a tool for releasing the creative potential and knowledge embedded in the society. It also has potential of employment generation in rural areas.

इस तरह से, समाज एसी विपत्तियों की संभावनाओं को कम या पूरी तरह से समाप्त करने में भी सफल हो सकता है। कृषि क्षेत्र में तो इसके विशेष योगदान हो सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी द्वारा उदीयमान तकनीकों, कीमतों, मौसम तथा विभिन्न फसलों के लिए मृदा की दशाओं की उपयुक्तता की जानकारी का प्रसारण हो सकता है। अपने आप में सूचना प्रौद्योगिकी कुछ भी नहीं बदल सकती, किंतु यह समाज में सृजनात्मक संभाव्यता और उनके ज्ञान संचय के यंत्र के रूप में कार्य कर सकती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने की संभाव्यता भी है।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ORGANIC FARMING

In recent years, awareness of the harmful effect of chemical-based fertilisers and pesticides on our health is on a rise. Conventional agriculture relies heavily on chemical fertilisers and toxic pesticides etc., which enter the food supply, penetrate the water sources, harm the livestock, deplete the soil and devastate natural eco-systems.

धारणीय विकास और जैविक कृषि

कुछ वर्षों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूकता का प्रसार हुआ है। भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों पर आधारित है। ये विषाक्त तत्व हमारी खाद्य पूर्ति व जल स्रोतों में निःसरित हो जाते हैं और हमारे पशुधन को हानि पहुँचाते हैं।

such technology which is eco-friendly is organic farming. In short, organic agriculture is a whole system of farming that restores, maintains and enhances the ecological balance. There is an increasing demand for organically grown food to enhance food safety throughout the world.

एसी ही एक प्रौद्योगिकी को 'जैविक कृषि' कहा जाता है। संक्षेप में जैविक कृषि, खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैविक विधा से उत्पादित खाद्य पदाथों की माँग में वृद्धि हो रही है।

Benefits of Organic Farming:
Organic agriculture offers a means to substitute costlier agricultural inputs (such as HYV seeds, chemical fertilisers, pesticides etc.) with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on investment. Organic agriculture also generates income through exports as the demand for organically grown crops is on a rise.

जैविक कृषि के लाभ: जैविक कृषि महँगे आगतों (संकर बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों) के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर होती है। ये आगत सस्ते रहते हैं और इसी कारण इन पर निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। विश्व बाज़ारों में जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई माँग के कारण इनके निर्यात से भी अच्छी आय हो सकती है।

Since organic farming requires more labour input than conventional farming, India will find organic farming an attractive proposition. Finally, the produce is pesticide-free and produced in an environmentally sustainable way.

चूँकि जैविक कृषि में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होता है – अतः भारत जैसे देश में यह अधिक आकर्षक होगा। अंतत: ये उत्पाद विषाक्त रसायनों से मुक्त तथा पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधियों द्वारा उत्पादित होते हैं

Popularising organic farming requires awareness and willingness on the part of farmers to adapt to new technology. Inadequate infrastructure and the problem of marketing the products are major concerns which need to be addressed apart from an appropriate agriculture policy to promote organic farming. It has been observed that the yields from organic farming are less than modern agricultural farming in the initial years. Therefore, small and marginal farmers may find it difficult to adapt to largescale production. Organic produce may also have more blemishes and a shorter shelf life than sprayed produce.

जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों का प्रयोग करने में किसानों की इच्छाशक्ति और जागरूकता आवश्यक है। जैविक कृषि संवर्धन के लिए उपयुक्त नीतियों के अभाव के साथ-साथ उनके विपणन की समस्या पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समस्याएँ इस विधि को प्रोत्साहन देने में बाधक हैं। यह देखा गया है कि प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की उत्पादकता रासायनिक कृषि से कम रहती है।

Nevertheless, organic farming helps in sustainable development of agriculture and India has a clear advantage in producing organic products for both domestic and international markets.

CONCLUSION **It is clear that until and unless some spectacular changes occur, the rural sector might continue to remain backward. There is a greater need today to make rural areas more vibrant through diversification into dairying, poultry, fisheries, vegetables and fruits and linking up the rural production centres with the urban and foreign (export) markets to realise higher returns on the investments for the products. Moreover, infrastructure elements like credit and marketing, farmerfriendly agricultural policies and a constant appraisal and dialogue between farmers' groups and state agricultural departments are essential to realise the full potential of the sector.**

निष्कर्ष एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रक में पिछड़ापन बना रहेगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक प्रकार के उत्पादक कार्यों की ओर उन्मुख कर वहां एक नए उत्साह और स्फूर्ति का संचार करना आवश्यक हो गया है। ये कार्य हो सकते हैं: डेरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी उत्पादन और ग्रामीण उत्पादन वे केंद्रों व शहरी बाज़ारों (विदेशी निर्यात बाज़ारों सहित) के बीच संपर्क सूत्रों की रचना। इस प्रकार, कृषि उत्पादन में लगे निवेश पर अधिक प्रतिलाभ अर्जित करना संभव हो पाएगा। यही नहीं, आधारिक संरचना जैसे, साख एवं विपणन, कृषक-हित-नीतियां तथा कृषक समुदायों एवं राज्य कृषि विभागों के बीच निरंतर संवाद और समीक्षा इस क्षेत्रक की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में सहायक है।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

There is need to invent or procure alternate sets of eco-friendly technologies that lead to sustainable development in different circumstances. From these, each rural community can choose whatever will suit its purpose. First of all, then, we need to learn from, and also try out when found relevant, practices from the available set of 'best practice' illustrations (which means success stories of rural development experiments that have already been carried out in similar conditions in different parts of India)

नई पर्यावरण–मित्र प्रौद्योगिकी विकल्पों के अविष्कार या प्राप्ति की भी आवश्यकता है, ताकि विभिन्न परिस्थितियों का सामना होने पर भी हम धारणीय विकास की ओर अग्रसर हो पाएँ। इन विकल्पों में से प्रत्येक ग्राम्य समुदाय अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप चयन कर सकता है। अत: हमारा पहला काम तो सभी उपलब्ध विधियों में से सर्वश्रेष्ठ की पहचान कर उसे चुनना ही होगा (तात्पर्य ग्रामीण विकास के प्रयोग की उन सफल कहानियों से है, जो देश में विभिन्न क्षेत्रों में हो चुकी हैं),

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

- **Rural development is quite a comprehensive term but it essentially means a plan of action for the development of rural areas which are lagging behind in socio-economic development.**
- **There is a need for improving the quantity and quality of infrastructure in rural areas such as banking, marketing, storage, transport and communications etc. to realise its true potential.**

- ग्रामीण विकास अपने आप में एक बहुत विस्तृत शब्द है। पर मूल रूप से इसे सामाजिक आर्थिक विकास में पिछड रहे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की एक सुनियोजित कार्यविधि माना जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक संभाव्यता को पाने के लिए बैंकिंग, विपणन, भंडारण, परिवहन, संचार आदि की आधारिक संरचना के परिमाण और गुणवत्ता को सुधारना होगा।

RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास

- **Rural development is quite a comprehensive term but it essentially means a plan of action for the development of rural areas which are lagging behind in socio-economic development.**
- **There is a need for improving the quantity and quality of infrastructure in rural areas such as banking, marketing, storage, transport and communications etc. to realise its true potential.**

- पशुपालन, मत्स्य–पालन और अनेक गैर–कृषि कार्यों को अपनाया जाना चाहिए। इस विविधीकरण से न केवल कृषि के जोखिम कम होंगे बल्कि साथ ही हमारे विशाल ग्रामीण जनसमुदाय को उत्पादक धारणीय आजीविका के नए विकल्प भी सुलभ हो पाएँगे।
- पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय उत्पादन प्रक्रिया के रूप में आज जैविक कृषि का महत्व निरंतर बढ़ रहा है – इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।